

‘सरकार को राजनीतिक दृष्टि से भी ईमानदार व तटस्थ होना चाहिए, केवल संख्या बल से सही होना पर्याप्त नहीं’

सोनिया गांधी ने अखबार में संपादकीय लेख लिखकर, चुनाव के दौरान संसद का विशेष सत्र आहूत करने के निर्णय को चुनौती दी

कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकन चीता बारां के जंगलों में पहुँचा

छबड़ा, 13 अप्रैल (निसं)। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के बारां जिले के जंगलों में पहुँचा अफ्रीकन चीता “केपी-3” इन दिनों लगातार मूवमेंट कर रहा है। सोमवार को यह चीता छबड़ा के आलमपुरा क्षेत्र में पहुँच गया। इस

■ वन विभाग छबड़ा के आलमपुरा क्षेत्र में चीता “केपी-3” के मूवमेंट पर लगातार नज़र रख रहा है।

दौरान वन विभाग टीम ने लगातार उसके मूवमेंट पर नज़र बनाए रखा।

यह चीता पार्वती नदी किनारे होते हुए यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद उसे पेड़ों की छांव में आराम करते देखा गया और उसने आसपास के क्षेत्र में हल्की चहलकदमी भी की।

क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ के अनुसार, चीते की मौजूदगी की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को हो गई थी, जिसके चलते लोग उसे देखने के लिए उसुक नज़र आए। पूरे दिन चीते की गतिविधियाँ संबंधित क्षेत्र में ही सीमित रही।

वन विभाग द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है, ताकि चीते की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। यहाँ छबड़ा रेंज के साथ-साथ एमपी के वनकर्मी भी मौजूद हैं। निगरानी के दौरान छबड़ा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने जहाजों को चेतावनी देनी शुरू की कि ब्लॉकेड शुरू हो गया है

पर चेतावनी से एक बात साफ हुई की अगर कोई भी जहाज ईरानी “ऑयल” ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसे बमबारी से उड़ा दिया जाएगा

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 13 अप्रैल। डॉनल्ड ट्रम्प की होमरूम स्ट्रेट में नाकेबंदी की धमकी सोमवार शाम से शुरू हो गई है। यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

इस बीच, ट्रम्प ने ईरान युद्ध में एक नया मोर्चा खोल लिया है। इस बार, ट्रम्प ने पोप लियो चौदहवें के साथ विवाद खड़ा किया। पोप ने पहले ट्रम्प के ईरान युद्ध की आलोचना की थी। ट्रम्प ने खुद को एक शांत तस्वीर में ईसा मसीह के रूप में प्रस्तुत किया, और इस कदम ने लाखों ईसाइयों को नाराज़ कर दिया।

कुछ समय से, ट्रम्प ने पोप पर तीखे हमले किए हैं, यह कहते हुए कि वह विदेशी नीति या अपराधों के मामले पर बोलने के लिए उपयुक्त नहीं है। पोप का अपमान करना ट्रम्प के लिए कूटनीतिक मुसीबत और रणनीतिक गलती साबित हो सकता है, क्योंकि होमरूम नाकेबंदी की शुरुआत के साथ उन्होंने अपने

■ पर, सवाल यह उठ रहा है कि ये जहाज अगर रूस और चीन जा रहे होंगे तो भी क्या अमेरिका उन्हें उड़ा देगा।

■ अमेरिका का यह “ब्लॉकेड” ईरान के लिए गंभीर धमकी है। क्योंकि, युद्ध के दौरान भी ईरान अपना “ऑयल” बेचकर काफी राजस्व प्राप्त कर रहा था तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जैसे-जैसे ऑयल के दाम बढ़ने लगे। ईरान की आमदनी भी वैसे-वैसे बढ़ती जा रही थी।

■ अब यह आमदनी अगर बंद हो गई तो भारी आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। अतः ईरान ने पुतिन से बात की है, हस्तक्षेप करने के लिए।

आक्रमण को पूरी तरह से एक नए क्षेत्र में फैला दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नाकेबंदी का कदम खतरों और अज्ञात जोखिमों से भरा है। किन्हीं भी क्रूड तेल ले जाने वाले जहाजों या उर्वरक से लदे जहाजों की नाकेबंदी, जिनकी भारी मांग है, आगे और भी टकराव को जन्म दे सकती है। पहले से ही जटिल संघर्ष और बिगड़ सकता है और अन्य देश इसमें फंस सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही जहाजों को नाकेबंदी के बारे में संकेत दे चुका है। लेकिन सोचिए, अगर नाकेबंदी में चीन या रूस को क्रूड भेजने वाले जहाज शामिल हों, तो क्या अमेरिका उनकी यात्रा रोक सकता है? और यदि अमेरिका ने इन जहाजों को भी रोका, तो रूस या चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी? (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 13 अप्रैल। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेज़ी दैनिक में लिखे अपने एक कड़े संपादकीय में नरेन्द्र मोदी सरकार पर महिलाओं के आरक्षण बिल को राजनीतिक लाभ में बदलने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान महिलाओं के आरक्षण बिल पर नहीं, बल्कि परिसीमन (डीलिमिटेशन) पर केन्द्रित है। सरकार इस अवसर और बिल का इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को बिना जनगणना किए फिर से तय करने के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल अंकगणितीय रूप से सही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से निष्पक्ष और बेदाग दिखाई देना चाहिए।

■ सोनिया गांधी के लेख के अनुसार, सरकार की प्राथमिकता महिला आरक्षण नहीं है, बल्कि, संसद की सीटों का परिसीमन है तथा इस परिसीमन के जरिए सरकार दक्षिण भारत की संसदीय सीटों की संख्या कम करना है।

■ इस परिसीमन से दक्षिण भारत का राजनीतिक महत्व घट जाता है तथा कांग्रेस पार्टी को दक्षिण भारत की पार्टियों को बगावत के झंडे के नीचे एकत्रित करना है, और उनको यह समझाया जा रहा है, अगर वे एक झंडे के नीचे नहीं हुए तो राजनीति की दृष्टि से व प्रशासन की दृष्टि से अप्रसांगिक हो जाएंगे।

परिसीमन के दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल चुनावी लाभ लेने और चुनाव जीतने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। उनका एकमात्र उद्देश्य और प्राथमिकता यही है। चुनाव के बीच विशेष सत्र की आवश्यकता के खिलाफ बोलते हुए,

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने सही और गलत का ध्यान रखना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका एकमात्र ध्यान चुनाव जीतने पर है, और चुनाव आयोग सरकार के साथ पूरी तरह गठबंधन में है।

जनगणना और परिसीमन पर सरकार की यू-टर्न नीति स्पष्ट और उल्लेखनीय है, जो एक ऐसी सरकार के बारे में बहुत कुछ बता रही है, जिसका ध्यान केवल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ पर केन्द्रित है।

महिलाओं का आरक्षण बिल, जिसे 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो परिसीमन है।

कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए तीन दिवसीय सत्र में उपस्थित रहने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन ने अरुणाचल में “नामकरण” अभियान शुरू किया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम की आलोचना की और दोनों देशों के संबंधों में नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 10 अप्रैल। जब भारत सरकार खाड़ी संकट के संभावित और नकारात्मक आर्थिक प्रभावों में व्यस्त है, पूर्वी सीमाओं पर संकट बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जिलों, गांवों, पहाड़ों और नदियों के नाम बदलने के अभियान को फिर से जारी कर दिया है।

2025 के अंत तक, चीन ने अरुणाचल में 89 स्थानों के नाम बदलने के पांच बैच जारी किए हैं। यह प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई और 2021, 2023, 2024 और 2025 में जारी रही। चीन अरुणाचल को जोगनान या दक्षिण तिब्बत कहता है और अरुणाचल के लगभग 83,000 से 90,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर अपना क्षेत्रीय अधिकार जताता है। इसने 1914 के

■ पूरा विश्व ईरान वॉर की समस्याओं से त्रस्त है, खासकर भारत का पूरा ध्यान पैट्रोल व एलपीजी संकट से निपटने पर है, ऐसे में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नया नाम रखना शुरू कर दिया है।

■ चीन ने यह कार्यवाही 2017 में शुरू की थी तथा 2017 से 2025 तक नए नामों के 5 बैच जारी कर चुका है।

■ चीन में अरुणाचल को जोगनान या दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। चीन ने 1914 में शिमला समझौते के तहत बनी मैकमोहन रेखा को पहले ही टुकरा दिया है और वह अरुणाचल पर दावा जताता रहा है।

शिमला समझौते में ब्रिटिश भारत और चीन के बीच स्थापित मैकमोहन रेखा को खारिज कर दिया है। चीन पश्चिमी लद्दाख में अक्साई चिन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भी अपने क्षेत्रीय अधिकार का दावा करता है।

कांग्रेस ने विशेष सत्र के लिए व्हिप जारी किया

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। कांग्रेस ने लोकसभा के अपने सदस्यों को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि वे आगामी 16 से 18 अप्रैल तक होने वाली सदन की तीन दिवसीय विशेष बैठक में मौजूद रहें तथा पार्टी के रुख का समर्थन करें। कांग्रेस ने आधिकारिक बयान में कहा कि 16 से 18 अप्रैल तक

■ महिला आरक्षण अधिनियम एवं परिसीमन में जुड़े विधेयकों व संशोधनों को पेश करने के आयोजित किया जा रहा है विशेष सत्र।

लोकसभा में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार और मतदान होना है, इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए यह व्हिप उस वक्त जारी किया है, जब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेल, एलपीजी के बाद अब सल्फर आपूर्ति भी खतरे में

ईरान जंग का दुष्परिणाम सल्फर आपूर्ति पर भी पड़ रहा है, जो कि खाद, बैटरी, सेमीकंडक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 13 अप्रैल। जब घर-घर ईंधन की कीमतों और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर चिंता है, तब ईरान युद्ध के बीच, एक और धीमा, लेकिन गंभीर व्यवधान पृष्ठभूमि में उभर रहा है। यह व्यवधान सल्फर से जुड़ा है, जो उर्वरक, बैटरी, रसायन, धातु और यहां तक कि सेमीकंडक्टर के लिए एक आवश्यक मूल तत्व है।

यूरिया से लेकर कंप्यूटर चिप तक, सल्फूरिक एसिड उत्पादन लाइनों के लिए अनिवार्य है। हालाँकि, होमरूम स्ट्रेट के आसपास यह व्यवधान आपूर्ति में झटका पैदा कर रहा है, जो कारखानों के उत्पादन को धीमा कर सकता है और खाद्य कीमतों को बढ़ा सकता है।

मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, समुद्र में भेजी जाने वाली सल्फर का आधा भाग होमरूम

■ सल्फर की आपूर्ति बाधित हुई तो भारत में सरकार पर खाद सिस्टी का अतिरिक्त भार पड़ेगा, किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलेगी, खाद्यान्न महंगा हो जाएगा और रसायन व धातु निर्माण संयंत्रों की लागत भी बढ़ जाएगी।

■ मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के अनुसार, विश्व भर में सल्फर की कुल आपूर्ति का 50 प्रतिशत होमरूम से गुजरता है और 28 फरवरी के बाद से 44,000 कंपनियों के “शिपमेंट” अवरूद्ध हो चुके हैं।

स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इन हैड ब्रैंड स्ट्रीट की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, वॉर शुरू होने के बाद से 44,000 कंपनियों का एक एक शिपमेंट प्रभावित हुआ है।

सल्फर मुख्य रूप से तेल और गैस परिष्करण का बाय प्रॉडक्ट है। वैश्विक निर्यात का 45 प्रतिशत से अधिक खाड़ी देशों के पास है। मूल रूप से, किसी भी तेल व्यवधान का असर जल्दी ही

का व्यवधान भारी प्रभाव दिखा सकता है, जैसे सरकार के लिए उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ना, किसानों के लिए उच्च इनपुट लागत, आपूर्ति सघन होने पर खाद्य महंगाई का खतरा, रसायन और धातु उत्पादकों के लिए लागत में वृद्धि।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया, जो कि प्रमुख निकल उत्पादक है, अपनी सल्फर का लगभग 75 प्रतिशत मध्य पूर्व से आयात करता है। भारत भी उर्वरक से जुड़ी मांग के लिए इसी तरह की निर्भरता में बैठा है। इसलिए, ईरान संघर्ष लंबा चलता है तो यह दबाव बना रहता है। वास्तव में, द सौफान सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा किए गए हालिया शोध और विश्लेषण में निष्कर्ष निकला है कि उर्वरक आपूर्ति में व्यवधान जल्दी ही खाद्य सुरक्षा जोखिम में बदल सकता है।

भारत अपनी सल्फर आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात करता है, मुख्यतः यूरिया और फॉस्फेट उर्वरकों के लिए। किसी भी लंबी अवधि

बंगाल में एक्शन मोड़ में है ईडी

-जाल खंबाता- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 13 अप्रैल। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने कई घोटालों से जुड़े उच्च प्रोफाइल छापों और संपत्ति जब्तियों की श्रृंखला शुरू की है, जिनमें भर्ती घोटाला, जमीन

■ राज्य में ईडी ने कई घोटालों की लिस्ट बनाई है और उसके आधार पर तृणमूल नेताओं व सरकार के अफसरों पर धड़ाधड़ रैड कर रही है।

हड़पना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के गेहूँ का गबन शामिल है। मार्च के अंत और अप्रैल 2026 की शुरुआत में हुई गतिविधियों की तूफानी श्रृंखला में, केन्द्रीय एजेंसी ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अगर जीत का मार्जिन, काटे गए वोटर्स की संख्या से कम है तो हम हस्तक्षेप करेंगे’

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर के संबंध में दायर याचिकाओं के बारे में हो रही सुनवाई के दौरान बहुआयामी टिप्पणी की

-जाल खंबाता- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 13 अप्रैल। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने केवल पश्चिम बंगाल में ही एसआईआर के दौरान संदिग्ध मतदाताओं को “ताकिक असंगति” सूची बनाई।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने यह टिप्पणी की और कहा कि अब पश्चिम बंगाल में मतदाता विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच फंस गए हैं। न्यायमूर्ति बागची ने यह टिप्पणी उस समय की, जब चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि आयोग के नोटिसों का निर्णय करने वाले न्यायिक अधिकारियों के कुल मामलों का 47 प्रतिशत खारिज किया गया।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “यह अंतिम साधन को न्यायसंगत बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि साधन अंत को

न्यायसंगत बनाने के लिए है। यह राज्य और चुनाव आयोग के बीच कोई संघर्ष नहीं है। यह आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी नहीं है। यह तो मतदाता के दो पादों के बीच फंसने का मामला है। अदालतों ने केवल चुनाव को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप किया है, रोकने के लिए नहीं।”

लेकिन न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि जब तक “अत्यधिक संख्या में मतदाता (मतदान से) बहिष्कृत नहीं होते,” चुनाव के परिणामों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “यदि 10 प्रतिशत मतदाता वोट नहीं करते और जीत का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक है, तो... यदि यह 5 प्रतिशत से कम है तो हमें विचार करना होगा। पहले किसी

उम्मीदवार को अपील न्यायाधिकरण के सामने प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि किसी उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। कृपया यह न सोचें कि हम यह नहीं सोच रहे कि बहिष्कृत मतदाताओं का क्या होगा।” न्यायमूर्ति बागची ने पश्चिम बंगाल और बिहार में एसआईआर के बीच भिन्नताओं पर भी प्रकाश डाला, विशेषकर ताकिक असंगति सूची के निर्माण में।

उन्होंने कहा, “हमने संवैधानिक प्राधिकरण को मतदाता सूची को शुद्धता के मुद्दे में जाने की अनुमति दी है। आपके एसआईआर पर आपकी मूल ईसीआई अधिसूचना ने 2002 की सूची को नहीं छुआ। लेकिन आपकी ताकिक असंगति सूची अस्वीकरण का कारण 2002 की सूची आदि है। आपकी अधिसूचना उन लोगों को प्रभावित करती है, जो 2002 की सूची से संबंधित हैं, अर्थात् 2002 की सूची मानक है। अंतिम सूची में आपने 2002 की सूची के सदस्यों को नहीं हटाया। जब बिहार एसआईआर पर विचार हुआ, तो आयोग की प्रस्तुतियाँ स्पष्ट थीं कि 2002 की सूची के सदस्यों को कोई हस्ताक्षर देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया बिहार के मामले में

अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ देखें। आपने कहा था कि 2002 के मतदाता को दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं है।” जब चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील डी.एस. नायडू ने कहा कि लोगों को यह साबित करना होगा कि वे 2002 की सूची वाले ही व्यक्ति हैं, न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “अब आप पहले की प्रस्तुतियों में सुधार कर रहे हैं।”

न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों ने निर्णय प्रक्रिया के दौरान कुछ त्रुटियों की होंगी। उन्होंने कहा, “यदि आप दिन में 1000 दस्तावेज़ देखते हैं, और सटीकता 70 प्रतिशत है, तो इस गतिविधि को उत्कृष्ट माना जाना चाहिए। इसलिए त्रुटि की संभावना होगी और हमें एक मजबूत अपील न्याय मंच की आवश्यकता है।” मतदान के अधिकार को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हुए कहा कि सिलीगुड़ी और उसके आसपास का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य की सत्ताधारी पार्टी को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

उपदेश के बजाय वहीं ज्यादा हम करके सीखते हैं। -बर्क

पश्चिम बंगाल के चुनावों की वैधता पर प्रश्नचिन्ह

पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव 23 और 29 अप्रैल 2026 को होंगे। गत विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यह नारा दिया था कि "अब की बार 200 पार" और वह विधानसभा की कुल 294 सीटों में केवल 77 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसी प्रकार, गत लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने "अब की बार 400 पार" का नारा दिया और वह 240 पर आकर अटक गई। शायद, भाजपा को लगने लगा है कि उसकी लोकप्रियता में धीरे-धीरे कमी आ रही है और चुनाव जीतने का कोई दूसरा रास्ता ढूँढना होगा। संभव है, इसी सोच के चलते भाजपा ने एस आई आर का तरीका निकाला।

सबसे पहले एस आई आर अर्थात् स्पेशल इंटरसिव रिवीजन, बिहार चुनाव से ठीक पहले कराया गया। इसका खूब विरोध हुआ किंतु निर्वाचन आयोग की हठधर्मिता के कारण किसी की नहीं चली। सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दायर हुईं किंतु वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। बिहार में एन डी ए ने अच्छे बहुमत से चुनाव जीता और सरकार बनाई। बिहार की चुनावी सफलता से उत्साहित होकर भाजपा ने सभी राज्यों में एस आई आर कराने का निर्णय ले लिया।

पूरे देश में मतदाता सूचियों के "स्पेशल इंटरसिव रिवीजन" का कोई प्रावधान चुनाव संबंधी कानून में नहीं है, किंतु बिहार में पहली बार इसे अचानक करने की घोषणा की गई। जब एस आई आर की आड में लाखों लोगों के नाम कटने का काम शुरू हुआ तो विभिन्न राजनैतिक दल और स्वीच्छिक संगठनों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर कीं। इनकी अनेक बार सुनवाई हुई और माननीय न्यायाधीशों ने कई बार सुनवाई के दौरान मौखिक निर्देश भी दिए, किंतु न तो अंतिम फैसला दिया गया और न ही एस आई आर की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। कुल मिलाकर एस आई आर केवल मतदाताओं के नाम कटने का उपक्रम बन कर रह गया। जिन घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करने की आड में निर्वाचन आयोग, एस आई आर की जड़ पर अडा रहा, उनकी संख्या आखिर तक निर्वाचन आयोग नहीं बता पाया। यह संख्या कुछ सैकड़ों से अधिक नहीं थी और इन्हें भी देश से निकालने की कोई कार्यवाही भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा नहीं की गई। हां, इस प्रक्रिया में लाखों वैध मतदाताओं के नाम अवश्य कट गए। फलस्वरूप, एन डी ए को बिहार विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित सफलता मिली।

यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस आई आर की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है जब कि बहस पूरी हुए कई महिने हो गए हैं। इसी बीच पुडुचेरी, केरल और असम के चुनाव हो चुके हैं और अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे हैं जिनका परिणाम 4 मई, 2026 को आएगा।

सबसे ज्यादा विवादस्पद, पश्चिम बंगाल का एस आई आर रहा है। वहां पर तृणमूल कांग्रेस और विशेष कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एस आई आर का घोर विरोध किया। उनके द्वारा, विभिन्न प्रकार की वृत्तियां सामने लाई गईं। उच्चतम न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं उपस्थित हो कर बहस भी की।

एस आई आर में कई खामियां और समस्याएं सामने आने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने कोई प्रभावित दखल इसमें नहीं दिया। इसके कारण निर्वाचन आयोग, विशेष कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी मनमानी करने में सफल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण ही इनको हटाने का प्रस्ताव विपक्ष राजनैतिक दलों के द्वारा संसद में लाया गया किंतु उसे राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार, ज्ञानेश कुमार को एक प्रकार से अभ्यन्तन मिल गया है।

पश्चिम बंगाल की एस आई आर में लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम कटे, जिनमें से 64 प्रतिशत हिंदू और 34 प्रतिशत मुस्लिम हैं। इस कारण भाजपा जो हासिल करना चाहती थी, वह शायद तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता के कारण पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई है। चाहे एक मतदाता का नाम कटे या 90 लाख का, यह पूरी तरह मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। कहा जाता है कि मतदाता मिलकर सरकार चुनते हैं किंतु जिस प्रकार की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई, उससे तो ऐसा लगता है कि सरकार मतदाता चुन रही है कि कौन मतदाता रहेगा और कौन नहीं। जिन मतदाताओं के नाम कटे, उनमें कई प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित हैं। इनमें वे लोग भी हैं जिन्होंने एस आई आर की प्रक्रिया को संपादित कराया। संविधान की मूल प्रति में चित्रांकन का काम करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के पोते तक का नाम सूची में से कट गया है। कई न्यायाधीशों तक के नाम भी कटे हैं।

अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल का एस आई आर सर्वाधिक विवादस्पद रहा है। यहां अनेक अधिकारियों को जिनमें मुख्य सचिव और महानिदेशक पुलिस तक सम्मिलित हैं, को चुनाव आयोग द्वारा बदल दिया गया। "लॉजिकल डिस्क्रिप्सी" के नाम पर 27.16 लाख मतदाताओं के नाम कटे दिए गए हैं। उन पर सुनवाई करने हेतु लगभग 500 न्यायाधीशों को लगाया गया। ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है।

"लॉजिकल डिस्क्रिप्सी" की यह अवधारणा पहली बार निर्वाचन आयोग ने लागू की है। कई बार नाम को स्पेलिंग में गलतियां होती हैं या एक ही नाम कई प्रकार से लिखा जाता है। इसी को लॉजिकल डिस्क्रिप्सी का नाम दिया गया।

जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो सुनवाई के दौरान एक माननीय न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया कि यदि किसी का नाम मतदान की तारीख तक शांतिपूर्ण नहीं हुआ तो वे आगे चुनाव में वोट डाल सकते हैं। यह तर्क बिल्कुल विचित्र है कि किसी वैध मतदाता को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाया मतदाता सूचियों पर आई सभी आपत्तियों का निराकरण किए बिना चुनाव करवाना अवैध माना जाएगा।

27.16 लाख लाख संभावित वैध मतदाताओं के नाम कटने का अर्थ यह हुआ कि एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9000 लोगों के नाम कटे हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव में जीत - हार का अंतर 5000 से कम रहता है वहां पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकता है। इन लोगों को टिब्यूनल में अपील करने के लिए कहा गया है और 23 अप्रैल, 2026 को चुनाव है। यह संभव नहीं है कि इन पर निर्णय उससे पहले हो पाएगा। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को मतदाता सूची 'freeze' कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल के दोनों चरणों के नामांकन की अंतिम तिथि क्रमशः 6 और 9 अप्रैल को निकल चुकी है। अतः इसमें अब नाम कैसे जोड़े जाएंगे, यह स्पष्ट नहीं है।

किसी भी भारतीय नागरिक को उसके मतधिकार से वंचित करना और निर्वाचन आयोग द्वारा इसके बारे में कोई स्थिति तक स्पष्ट नहीं करना, एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या के समान है। मतदाता सूची किसी भी चुनाव का मूल आधार है और वहीं जब अशुद्ध होगी तो कैसे चुनाव को शुद्ध कहा जाएगा?

जब चुनाव के बाद उच्च न्यायालय में निर्वाचन को चुनौती दी जाएगी तो, स्वाभाविक रूप से उच्च न्यायालय के पास उस चुनाव परिणाम को निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा। इन सभी परिस्थितियों में यह प्रश्न तो उठता ही है कि निर्वाचन आयोग को क्या जल्दी थी एस आई आर करने की? क्यों वह देश के नागरिकों और राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का कोई उतर सर्वजनिक रूप से नहीं दे रहा है?

राज्यों की एस आई आर के लिए निर्धारित समय सीमा इतनी अत्यावहारिक थी कि उसे कई बार निर्वाचन आयोग को बढ़ाना पड़ा। वर्तमान निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनैतिक दलों का आरोप है कि वे अपने कार्य और व्यवहार से भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि न्याय न केवल होना चाहिए अपितु होता हुआ दिखाई भी ऐसा देना चाहिए। एस आई आर में न तो न्याय हुआ न होता हुआ दिखाई दिया।

यह सही है कि चुनावों के दौरान राज्य का प्रशासन सीधा निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है, किंतु ऐसा लगता है कि इस निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल के इशारे पर सारे काम किए हैं।

निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है किंतु इसका अर्थ उसके द्वारा मनमानी करना नहीं हो सकता। उसका यह दायित्व बनता है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के द्वारा उठाया गए प्रश्नों का समुचित प्रकार से समाधान करे। ज्ञानेश गुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर कोई उतर तक नहीं दिया। यही नहीं तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद और अन्य प्रतिनिधि ज्ञानेश गुप्ता से मिलने के लिए गए तो उन्होंने 5 मिनट में इन लोगों को अपने कमरे से बाहर निकाल कर मीटिंग समाप्त की घोषणा कर दी। निर्वाचन आयोग का, निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति यह व्यवहार लोकतंत्र में किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत चाहे किसी की क्यों ना हो, निर्वाचन आयोग के कारण वहां के अनेक मतदाता अपने मतधिकार से वंचित तो हो ही गए हैं। इसे केवल लोकतंत्र की हार ही कहा जाएगा। ज्ञानेश कुमार अथवा निर्वाचन आयोग को, इस प्रकार का निरंकुश व्यवहार करने का अधिकार न संविधान देता है न लोकतांत्रिक व्यवस्था। यदि वह ऐसा कर पाए है तो केवल सत्ताधारी दल भाजपा के पूर्ण संरक्षण के कारण। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की वैधता पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही गया है। चुनाव परिणाम आने के बाद भी कई याचिकाएं लगने की संभावना है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने एस आई आर के सहारे ही चुनावी वैतरणी पार करने का निर्णय लिया है।

-अतिथि सम्पादक,
राजेश्रुत भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



मानसिंह मोणा

राजस्थान के बाड़मेर जिले की भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसा सुंदरा गाँव एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना है। आजादी के बाद पहली बार इस दूरस्थ रेगिस्तानी

ऑर्गन, ब्लड एवं आई डोनेशन और धार्मिक जड़ता : जब आस्था मानवता पर भारी पड़ने लगे



सुनील दत्त गोयल

भारत में अंगदान और रक्तदान पर चर्चा अब केवल स्वास्थ्य या जागरूकता तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह सामाजिक व्यवहार और धार्मिक व्याख्याओं के टकराव का विषय बन चुकी है। ऑर्गन, ब्लड और आई डोनेशन जैसे जीवनरक्षक विषयों पर जब हम आंखों की ज़मीन पर खड़े होकर सोचते हैं, तो एक असहज सच्चाई सामने आती है - हमारे समाज में जागरूकता से ज़्यादा भ्रम है, और सेवा से ज़्यादा संकोच।

खासतौर पर यह आरोप बार-बार सामने आता है कि कुछ समुदायों में - विशेषकर मुस्लिम समाज के एक हिस्से में - अंगदान और रक्तदान को लेकर हिचक या इंकार देखने को मिलता है, और इसके पीछे धार्मिक कारण बताए जाते हैं। लेकिन जब हम इस मुद्दे को धारणाओं से हटाकर तथ्यों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो कई महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आते हैं।

वैश्विक परिदृश्य: दुनिया क्या कहती है?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार - हर साल दुनिया पर में 1.5 लाख से अधिक अंग प्रत्यारोपण किए जाते हैं - जबकि वास्तविक ज़रूरत इससे 10 गुना अधिक है - रक्तदान की मांग हर देश में निरंतर बढ़ रही है, विशेषकर आपातकालीन सेवाओं, कैंसर, थैलेसेमिया, किडनी और ट्रांमा मामलों में।

यूरोप और अमेरिका के कई देशों में ऑर्गन डोनेशन को धर्म नहीं, नागरिक कर्तव्य माना जाता है। स्पेन

जैसे देशों में ऑट-आउट मॉडल लागू है, जहाँ मृत्यु के बाद अंगदान स्वतः मान्य होता है, जब तक व्यक्ति ने मना न किया हो।
भारत की हकीकत: ज़रूरत बहुत, दान कम
नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं: - भारत में हर वर्ष लगभग 5 लाख लोग ऑर्गन की कमी के कारण जान गंवा देते हैं - भारत का ऑर्गन डोनेशन रेट 0.5 प्रति मिलियन जनसंख्या है - जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 20-40 प्रति मिलियन तक है।

ब्लड डोनेशन के मामले में भी:
- भारत को हर साल लगभग 1.4 करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है - स्वीच्छिक रक्तदान अब भी ज़रूरत से बहुत कम है यहाँ यह तथ्य नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि स्वीच्छिक रक्तदान शिविरों की रीढ़ सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज को छोड़कर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई एवं अन्य संस्थाएँ सक्रिय हैं।

वैश्विक इस्लामी परिप्रेक्ष्य:
जहाँ जीवन बचाना प्राथमिकता है दुनिया के कई प्रमुख मुस्लिम-बहुल देशों - जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), तुर्क और ईरान में: - अंगदान पूरी तरह कानूनी और संस्थागत रूप से स्वीकृत है - ब्लड बैंक सरकार द्वारा संचालित और व्यवस्थित हैं - इस्लामी विद्वानों द्वारा कई बार स्पष्ट किया गया है कि ज़रूरतमंद की जान बचाना सर्वोच्च कर्तव्य (फ़र्ज़) है - ईरान जैसे देश में तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिस्टम इतना विकसित है कि वह क्षेत्र में मॉडल माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि इस्लाम की मूल शिक्षाओं में अंगदान या रक्तदान निषेध नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार

टयूबवेल की बेकार साबित हुए मजबूरी में लोगों को 15-20 किलोमीटर दूर अन्य गाँवों से पानी ढोकर लाना पड़ता था।
युद्ध और विस्थापन की पीड़ा:
- भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 और भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान इस सीमा क्षेत्र के गाँव को खाली करवा दिया गया था। ऐसे में सुंदरा के लोगों ने न सिर्फ प्राकृतिक कठिनाइयों, बल्कि ऐतिहासिक चुनौतियों का भी सामना किया।

नर्मदा का नीर: एक असंभव को संभव करने वाली परियोजना
इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या - पेयजल-का समाधान बना नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना। सरदार सोरोवर बांध से शुरू होकर नर्मदा का पानी 728 किलोमीटर की लंबी दूरी तक सर सुंदरा तक पहुँचा। करीब 513

यहाँ का भूजल इतना खारा था कि इसानों के साथ-साथ पशु भी उसे पीने से कतराते थे। सरकार द्वारा लगाए गए

करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 200 से अधिक गाँवों तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया, 16 बड़े जल संग्रहण केंद्र बनाए गए, कई पंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए, 80 से अधिक एलिवेटेड सर्विस रिज़र्वायर तैयार किए गए, रेत के ऊँचे-ऊँचे टीलों को काटकर पाइपलाइन बिछाना, बिजली की कमी और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा प्रतिबंधकृद्धन सभी बाधाओं को पार करते हुए यह परियोजना पूरी की गई।

जब सपना हकीकत बना:
- सुंदरा के लोगों के लिए यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। 80 वर्षीय महिलाओं ने पहली बार अपने घर के सामने मोटे पानी का नल देखा। दशकों तक खारा पानी पीने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ाक़दत पीले होना, हड्डियाँ कमजोर

होना और समय से पहले बुढ़ापा आम बात थी।
गाँव की महिलाओं को रोजाना कई किलोमीटर दूर पानी लाने की मजबूरी से अब मुक्ति मिल गई है। अब न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
नई शुरुआत की ओर कदम:
- आज सुंदरा गाँव में नल से बहता पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि विकास, सम्मान और बेहतर जीवन का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी बताती है कि स्वीच्छीय योजना, दृढ़ संकल्प और तकनीकी प्रयासों से देश के सबसे कठिन इलाकों में भी बदलाव संभव है।

-मानसिंह मोणा,
उप निदेशक (जनसम्पर्क)
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर

इसे स्वीकार किया गया है। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है: जब अन्य इस्लामी देश विज्ञान और मानवता के साथ खड़े हो सकते हैं, तो भारत में कुछ समूह समाज को भय और संदेह की ओर क्यों धकेल रहे हैं?

भारत में अलग व्यवहार क्यों?
यही सबसे बड़ा प्रश्न है - अगर वही धर्म: - सऊदी अरब में अंगदान की अनुमति देता है - दुबई में ब्लड डोनेशन कैम्प चलाता है - ईरान में ट्रांसप्लांट सिस्टम को समर्थन देता है

तो भारत में कुछ लोग इसे धार्मिक रूप से गलत कैसे बता देते हैं? यहाँ समस्या धर्म नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर फैली गलतफहमियाँ, अधूरी जानकारी और सामाजिक नेतृत्व की कमी है। 'काफिर' तर्क और उसका व्यावहारिक विरोधाभास अक्सर एक तर्क यह भी सुनने को मिलता है कि इस्लाम में काफिर (गैर-मुस्लिम) से संबंध सीमित रखने की बात कही जाती है, और इसी आधार पर अधिकतर लोग रक्तदान या अंगदान से बचते हैं।

लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है: अगर काफिर से लेना या देना गलत है, तो फिर - अस्पताल में इलाज के दौरान - ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय - ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय यह भेदभाव क्यों नहीं किया जाता? जिन्हें तुम काफिर समझते हो, उनका खून अगर तुम्हारी रगों में बह रहा है, तो ये खुदा को कैसे मंज़ूर होगा? वास्तविकता यह है कि: - आपात स्थिति में मरीज धर्म नहीं, जीवन देखता है - डॉक्टर मान शरीर की ज़रूरत देखता है, न कि आस्था इसलिए यह कहना कि लेना ठीक है, लेकिन देना गलत है न तो धार्मिक दृष्टि से तार्किक है और

न ही नैतिक दृष्टि से सही है।
आस्था बनाम अतिवाद: समस्या कहाँ है?
यह लेख किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि धार्मिक कट्टरता (रिज़िडियस एक्सट्रेमिज़म) के विरुद्ध है - जो आस्था को डर और भ्रम में बदल देती है।

भारत में यह देखा गया है कि:
-कुछ कट्टरपंथी विचारधाराएँ ब्लड और ऑर्गन डोनेशन को धार्मिक रूप से संदिग्ध बताकर लोगों को रोکتती हैं - जबकि इस्लामी जगत के कई देशों में यही कार्य धार्मिक अनुमति और सरकारी समर्थन के साथ हो रहा है

यह विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है - अगर धर्म वही है, तो व्यवहार इतना अलग क्यों? धार्मिक कट्टरता का दुष्परिणाम धार्मिक कट्टरता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि: -वह व्यक्ति को सोचने से रोक्तती है -समाज को टुकड़ों में बाँटती है -आज विज्ञान को षड्यंत्र बताती है

जब कट्टरता यह सिखाती है कि:
-फर्ला धर्म का खून स्वीकार्य नहीं -अंगदान से आत्मा को नुकसान होगा तो वह न केवल संविधान के विरुद्ध जाती है, बल्कि मानवता के भी विज्ञान का स्पष्ट उल्टर मेडिकल साइंस के अनुसार: -रक्त का कोई धर्म नहीं होता -अंगों पर कोई मजहबी टैग नहीं लगा होता

अस्पताल में मरीजों की जान बचाते समय:
-डॉक्टर धर्म नहीं पूछता -ब्लड बैंक जाति नहीं देखता तो फिर समाज में यह भेद क्यों? कानून की भूमिका: अब सख्ती क्यों ज़रूरी है? आज भारत में: -ब्लड डोनेशन पूरी तरह

स्वीच्छिक है -ऑर्गन डोनेशन में जागरूकता और प्रक्रिया दोनों कमजोर हैं -अब समय आ गया है कि: -स्कूल और कॉलेज स्तर पर ऑर्गन डोनेशन शिक्षा अनिवार्य हो -अस्पतालों में डिजिटल ऑर्गन डोनर रजिस्ट्रेशन हो -मृत्यु के बाद अंगदान पर ऑट-आउट मॉडल पर गंभीर बहस हो

-और जानबूझकर भ्रम फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो -असह्य और विरोध नहीं, जीवन-संरक्षण नीति है।

जीवन सबसे बड़ा धर्म
भारत एक ऐसा देश है जहाँ: -सभी धर्मों की मूल भावना सेवा और करुणा है -लेकिन अतिवाद इन मूल्यों को धुंधला कर देता है -आज ज़रूरत है: -आस्था को विवेक से जोड़ने की -धर्म को मानवता से ऊपर न रखने की -और यह समझने की कि जीवन बचाना किसी एक धर्म का नहीं, पूरे समाज का कर्तव्य है

क्योंकि अंततः, जिस खून से किसी की साँसें चलती हैं, वह केवल ईंसान का खून होता है। अंतिम प्रश्न: समाज खुद से जवाब मांगे

आज समय आ गया है कि समाज खुद से कुछ कठोर प्रश्न पूछे: -क्या हम अपने ही लोगों को केवल भ्रम के कारण मरने देंगे? -क्या हम दान लेने में तो आगे रहेंगे, लेकिन देने से पीछे हटेंगे? अगर लेना जायज़ है, तो देना गुनाह कैसे हो गया -या फिर यह सिर्फ संकीर्ण स्वार्थी सोच है?

-क्या हम धर्म के नाम पर मानवता को कमजोर करेंगे? यदि इन सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर बदलाव भी हमें ही लाना होगा। -रोटैरियन सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इम्पीरियल चैबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।



राशिफल

मंगलवार 14 अप्रैल, 2026

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2083, शतभिषा नक्षत्र सायं 4:06 तक, शुक्ल योग दिन 3:39 तक, कोलव करण दिन 12:4 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरु-मिथुन, शुक-मेघ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज त्रिपुंकर योग सायं 4:06 से रात्रि 12:13 तक है। आज वैशाख संक्रांति, सूर्य मेघ राशि में प्रवेश प्रातः 9:32 पर करेगा। पुष्य काल दिन 3:36 तक है। मीन मास समाप्त होगा। आज पंचक, वैशाखी, विशु (केरल) है। आज डा.अम्बेडकर जयन्ती है।
श्रेष्ठ चौघड़ियाँ: चर 9:18 से 10:52 तक, लाभ-अमृत 10:52 से 2:02 तक, शुभ 3:37 से 5:11 तक।
राहुकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:46

मेघ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार में सुख-सुविधाएँ बढ़ेंगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशवासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क
चन्द्रमा अशुभ भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मानसिक तनाव रहेगा।

मकर
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बने लगे। अटका धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सुविधाएँ बढ़ेंगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सांस्कृतिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कुंभ
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनासुचारु बने लगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कन्या
आर्थिक विवादों का निपटारा हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।

मीन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर 135वां जयन्ती समारोह

पेंशन एवं पालनहार योजना के लाभार्थियों को 1,363 करोड़ रुपए का हस्तान्तरण

मुख्य अतिथि

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

लोकार्पण / शिलान्यास / शुभारम्भ / वितरण

10 छात्रावास भवनों का
लोकार्पण एवं 17 का शिलान्यास

स्वयंसिद्धा परिसर, जामडोली
में लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन

AI आधारित हैल्पडेस्क
'समाधान साथी' का शुभारम्भ

कन्यादान योजना के
लाभार्थियों को राशि वितरण

दिव्यांगों को कृत्रिम
सहायक अंग वितरण

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे के साथ एम.ओ.यू.

14 अप्रैल, 2026 | प्रातः 10.30 बजे | भवानी निकेतन परिसर, सीकर रोड, जयपुर

13 मिनट में पार किए 45 लाख रुपए की चांदी के गहने

जयपुर (कासं)। सदर इलाके में अज्ञात नकबजान एक आभूषण कारखाने पर निशाना साधते हुए महज 13 मिनट में 45 लाख रुपए की चांदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। वारदात कि जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एफएसएल टीम की सहायता से घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर नकबजानों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चांदपोल बाजार स्थित जाट के कुएं का रास्ता निवासी व्यापारी बलराम सोनी ने मामला दर्ज कराया है कि रेलवे स्टेशन रोड पर दिगंबर जैन मंदिर के पास उनका आभूषण निर्माण कारखाना है। जिसके पीछे जैन मंदिर स्थित है। अज्ञात नकबजानों ने मंदिर परिसर का ताला तोड़ा और वहां से कारखाने के अंदर घुसे। कारखाने के अंदर घुसने के बाद अज्ञात नकबजान काउंटर में रखी 20 किलो चांदी के आभूषण कटौत और थैलों में भरकर ले गए।

अश्लेश पंवार व मानसिंह को बधाई दी

जयपुर। सहकारिता विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी अश्लेश पंवार एवं मानसिंह शेखावत ने पांचवीं ओपन सेन्ट्रल एशियन हैण्डबॉल पुरुष चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। अश्लेश पंवार एवं मानसिंह शेखावत ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकन्द में 31 मार्च से 5 अप्रैल तक किया गया था। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था।

जामडोली से लापता 14 वर्षीय बालक ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे मिला

जयपुर (कासं)। राजधानी की जामडोली थाना पुलिस ने सुनैती दिखते हुए तीन दिन से लापता एक नाबालिग बालक को सुरक्षित दस्तयाव कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजिता शर्मा ने बताया कि सुमेल (जामडोली) निवासी 14 वर्षीय बालक विक्रान्त बुनकर पुत्र बनवारी लाल बुनकर गत 9 अप्रैल को अपने घर से बिना बताए कहीं निकल गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर थाना जामडोली में अपहरण की धाराओं (137 (2) बीएएस) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (आदर्श नगर) लक्ष्मी सुधार के सुपरविजन में थानाधिकारी रतन सिंह कविया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने शहर के



विभिन्न बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। साथ ही तकनीकी सहायता और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बालक की लोकेशन ट्रैक की गई। पुलिस टीम की कड़ी मेहनत के बाद बालक विक्रान्त को दिल्ली बाईपास रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे से सकुशल ढूंढ निकाला। पूछताछ में सामने आया कि बालक अपनी स्वेच्छा से घर छोड़कर गया था और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या अपराध घटित होना नहीं पाया गया है।

जयपुर में यादगार से सांगानेर तक बनेगा माँडल ट्रैफिक कॉरिडोर

देश के प्रमुख महानगरों की यातायात व्यवस्था का अध्ययन करके बनाई जयपुर की रूपरेखा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेकर एडिशनल डीसीपी के पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता सुधार के लिए उनकी वर्दी बदलेगी। अभी व्हाइट रंग से बदलते हुए नए कलर की वर्दी दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस बेड़े के ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को 20 माँडलफाइंड मोटरसाइकिलें मिलेंगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने देश के प्रमुख महानगरों की यातायात व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं फील्ड विजिट करने के बाद समीक्षा कर व्यापक सुधार की रूपरेखा बनाई है। इस इंटेलेजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को चरणबद्ध रूप से शहर में लागू किया जाएगा। साथ ही अजमेरी गेट स्थित यादगार से सांगानेर तक माँडल ट्रैफिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। ट्रैफिक की निगरानी एवं जाम की स्थिति का आंकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा।

प्लान के तहत शुरूआती चरण में टोंक रोड को यादगार से सांगानेर तक माँडल ट्रैफिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर पर नगर निगम और जेडीए के कॉन्डिशन से अलग-अलग काम करवाए जाएंगे।

इसमें सड़क डिजाइन में आवश्यक सुधार करते हुए असुरक्षित कटर्स (मीडियन ओपनिंग) को बंद किया जाएगा। पैदल यात्रियों के लिए सेफ फुटपाथ का निर्माण, यू-टर्न और क्रॉसिंग

- ट्रैफिक पुलिस की बदलेगी वर्दी, यातायात जाम की स्थिति का आंकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश पर इस इंटेलेजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को चरणबद्ध रूप से राजधानी में लागू किया जाएगा।

पाँदस का टेक्निकली कार्य शामिल किए जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल को भी रियल टाइम यातायात दबाव के अनुसार डायनेमिक बनाया जाएगा।

ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को मिलेंगी 20 बाइक

जयपुर ट्रैफिक पुलिस के बेड़े में 20 माँडलफाइंड मोटरसाइकिलें भी शामिल होंगी। यह मोटरसाइकिल ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को मिलेंगी। इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इससे ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तेज मुवमेंट कर सकेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अभय कमांड सेंटर से जुड़े अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की स्थापना शामिल है। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।

72 ट्रैफिक बीट में बंटेगी जिम्मेदारी

जयपुर शहर को 72 ट्रैफिक बीट्स में विभाजित करने से प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित हो सकेगी। प्रत्येक बीट में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनकी सेफ फुटपाथ का निर्माण, यू-टर्न और क्रॉसिंग

ऑवर्स में प्रभावी यातायात नियंत्रण एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। यातायात प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बीट स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं जवाबदेही की प्रणाली विकसित होगी।

ट्रैफिक पुलिस में अफसरों के पदों की संख्या बढ़ाई

नए प्लान के तहत ट्रैफिक पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव होगा। अब जयपुर शहर में अब एडोसीपी (ट्रैफिक) के पदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने से जयपुर शहर के प्रत्येक पुलिस जिले में एक-एक एडोसीपी (ट्रैफिक) की तैनाती सुनिश्चित होगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा बेहतर निरीक्षण संभव होगा।

इसी प्रकार एसीपी (ट्रैफिक) के पदों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 8 करने से प्रत्येक पुलिस जिले में 2 एसीपी (ट्रैफिक) नियुक्त किए जाएंगे। इससे निगरानी, प्रवर्तन एवं समन्वय का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा। वहीं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 करने से प्रत्येक पुलिस जिले में औसतन 5 टीआई की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही एवं तैनाती को तर्कसंगत बनाया जाएगा। इससे पीक

4 अति. पुलिस उपायुक्तों को ट्रैफिक मैनेजमेंट का जिम्मा

जयपुर। राज्य सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर पुलिस बेड़े में प्रशासनिक फेरबदल किया है। जारी इन आदेशों के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेंट में चार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों (एडोसीपी) के स्थापना और पदस्थापन किए गए हैं। इस बदलाव को मुख्य केंद्र यातायात शाखा और मुख्यालय उत्तर रहे हैं। वरिष्ठ शासन उप सचिव (पुलिस) रमेश कुमार शर्मा द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार एसओजी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हरिप्रसाद सोमानी को अब अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात (उत्तर) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चतुर्थ बटालियन आरएसी के कमांडेंट समीर कुमार को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात (पश्चिम) के पद पर तैनात किया गया है। पीसीपीएनडीटी इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हेमन्त कुमार जाखड़ अब अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात (पूर्व) के रूप में कार्यभार संभालेंगे और यातायात शाखा (उत्तर) में कार्यरत सरिता बड़गुजर का तबादला कर उन्हें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय-उत्तर) पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ शासन उप सचिव (पुलिस) रमेश कुमार शर्मा द्वारा जारी इन आदेशों में सभी अधिकारियों को अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर तुरंत प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस फेरबदल से शहर की यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी।

“राजस्थान यूथ डायलॉग” में मुख्यमंत्री ने किया संवाद

युवा शक्ति ही देश की दिशा तय करेगी : भजनलाल शर्मा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘माय भारत बजट क्वेस्ट-राजस्थान यूथ डायलॉग’ कार्यक्रम में वचुंअल माध्यम से प्रतिभागियों से संवाद किया।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं और वही देश की दशा और दिशा तय करते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने का आह्वान करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हर कदम पर साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘माय भारत बजट क्वेस्ट-राजस्थान यूथ डायलॉग’ कार्यक्रम से संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और युवा नीति लागू करने जैसे निर्णयों के लिए सरकार का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 75 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें

राज्य के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने 4 लाख भर्तियों के लक्ष्य के तहत अब तक एक लाख 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि निजी क्षेत्र में 3 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर 420 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दो वर्षों में 351 से अधिक परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शी तरीके से करवाई हैं।

‘मई-जून में गर्मी पड़ेगी और बाद में बारिश होगी, इसलिए फिलहाल चुनाव नहीं करवा सकते’

पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव में देरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने चुनाव कराने की तिथि को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें राज्य सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी महीनों में चुनाव करना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि, मई-जून में गर्मी पड़ेगी और बाद में बारिश होगी, इसलिए फिलहाल चुनाव नहीं करवा सकते।

महाविधवा राजेन्द्र प्रसाद की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अभी तक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है और संविधान के अनुच्छेद 243-डी एवं 243-टी के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा अन्य पिछड़ा वर्ग

अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि “ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर तक आने की संभावना है। इसके बाद आरक्षण तय कर तुरंत चुनाव अधिसूचित कर दिए जाएंगे।”

के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है। इसलिए राज्य में पंचायत व निकाय चुनाव अभी नहीं हो सकते। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर तक आने की संभावना है। ऐसे में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही आरक्षण तय कर तुरंत चुनाव अधिसूचित कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह प्रार्थना पत्र पूर्व विधायक संयम लोधा और गिराज देवदा की जनहित याचिकाओं में दायर किया है।

राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए करीब 1.26 लाख और ग्रामीण पंचायती संस्थाओं के लिए करीब

2.50 लाख मतदान कर्मचारियों की जरूरत होगी। इनमें करीब 70 फीसदी शिक्षाकर्मी रहेंगे। फिलहाल स्कूलों में 1 अप्रैल 2026 से शैक्षणिक शुरू हो चुका है और मई-जून में प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। वहीं जुलाई से सितंबर तक मानसून और कृषि कार्यों में आमजन व्यस्त रहेगा।

इस दौरान चुनाव कराना न तो कर्मचारियों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के स्वास्थ्य के लिए उचित है और न ही व्यावहारिक। वहीं कई

अनसेफ पाए जाने पर 17 खाद्य उत्पाद प्रतिबंधित

प्रदेशभर में वितरण, विक्रय और डिस्पले पर दो माह तक रोक

जयपुर। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने मिलावटी 17 खाद्य उत्पादों को प्रदेशभर में 2 माह तक प्रतिबंधित कर दिया है। राज्य में इनके वितरण, विक्रय और डिस्पले पर रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों विभाग ने इन तमाम सामग्रियों के सैंपल लिए थे, जो कि जांच में अनसेफ पाए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि युवाओं को बचाने के लिए केंसर बादी, बंगाल गोल्ड ब्रांड की चाय, शुगर बॉयल्ड कैफेक्शनरी “नगद नारायण” डेयरी डेयरी प्रीट, हरियाणा और श्री थेयरी ब्रांड ब्रांड का ची, श्री साई मसालेवाला ब्रांड की हल्दी, घेनु सरस ब्रांड ची, ईजी डेयरी ब्रांड ची, भोग विनायक ची, ब्रांड स्नेक टेक का रोस्टेड चना, हरियाणा क्रोम ब्रांड ची, श्री भैरव प्रसाद ची, जयश्री कृष्णा ची, डेयरी संस ची तथा बालाजी ब्रांड का तीखा मीठा मिक्स नमकीन खाद्य

सुरक्षा विभाग की जांच में असुरक्षित पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमल्ल ने बताया कि खाद्य व्यापारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46(4) की निर्धारित अवधि में पुनः जांच के लिए अपील करने के बाद रोक प्रतिबंध प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनसेफ प्राप्त होने या धारा 46(4) की अवधि में अपील नहीं करने पर इन खाद्य पदार्थों के रिकॉल की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

अतः आमजन को सलाह दी गई है कि वे इन खाद्य पदार्थों की खरीद और उपयोग नहीं करें। अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि विनायक ची, ब्रांड स्नेक टेक का रोस्टेड चना, हरियाणा क्रोम ब्रांड ची, श्री भैरव प्रसाद ची, जयश्री कृष्णा ची, डेयरी संस ची तथा बालाजी ब्रांड का तीखा मीठा मिक्स नमकीन खाद्य

एयरपोर्ट से हल्दी घाटी सर्किल की 100 फीट चौड़ी रोड के निर्माण का आदेश वापस लिया हाईकोर्ट ने

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से प्रताप नगर के हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौड़ी रोड के निर्माण के संबंध में छह माह पहले दिए अपने आदेश को वापस ले लिया है। एडिजेंट सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित ने यह आदेश अजयमार्ग निर्माण संघर्ष समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

रमेश चन्द्र मीणा व अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि खंडपीट ने जेडीए को निर्देश दिए थे कि साल 2011 के सेक्टर प्लान के अनुसार नया अलाइनमेंट के अनुसार रोड निर्माण किया जाए। वहीं रोड का जो हिस्सा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है, उसके निर्माण का खर्चा हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम से वसूला जाए। यदि उनसे खर्चा नहीं मिले तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर ही रोड का निर्माण करे, केवल खर्चे के आधार पर ही रोड का निर्माण कार्य नहीं रोका जाए। इसके अलावा खंडपीट ने कहा था कि यदि इस रोड के संबंध

में किसी भी कोर्ट में कोई स्टे चल रहा है तो वह इस आदेश में ही समाहित हो जाएगा। वहीं इस रोड के निर्माण कार्य के संबंध में कोई भी डिब्रिगल या कोर्ट किसी के दावे को मंजूर नहीं करे। इसके अलावा रोड के निर्माण के दौरान चाहें तो पुलिस को मदद भी ली जा सकती है। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को कहा कि एडिजेंट सीजे बतौर वकील इस याचिका में पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी ओर से मामले की सुनवाई करना उचित नहीं था। अदालत की ओर से आदेश देने के बाद उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है। ऐसे में खंडपीट इस आदेश को वापस ले।

जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीट ने आदेश वापस लेते हुए इसकी सुनवाई दूसरी खंडपीट को करने को कहा है। याचिका में कहा था कि सेक्टर प्लान में यह रोड 100 फीट की है, लेकिन कई सालों से इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण ही हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक व दो को आज तक विकसित नहीं कर पाया है। इसलिए रोड का निर्माण कराया जाए।

शातिर नटवरलाल से पुलिस ने 90 लाख रु. बरामद किए

जयपुर। मुरलीपुरा पुलिस ने शातिर ठगों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शत-प्रतिशत राशि बरामद कर ली है। इनकम टैक्स रेंज का खीफ दिखाकर लुटें गई राशि की बरामदगी के लिए पुलिस ने आरोपी के पैतृक आवास तक दबिशा दी।

डॉसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी बाबूलाल वर्मा उर्फ बी.एल. गोयल को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ठगी की शेष राशि अपने मूल निवास चूरू में छिपा रखी है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने चूरू स्थित उसके घर पर दबिशा देकर 12 लाख 50 हजार रुपये और बरामद किए। अनुसंधान में यह चौकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी ने ठगी की राशि का उपयोग अपना पुराना कर्मचारी करने में किया था। उसने केनारा बैंक (छुंछुन) में अपने गोल्ड लोन की अदायगी के लिए 25 लाख रुपये जमा करवाए थे।

विधानसभा को आर.डी.एक्स. से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा

सुरक्षा एजेंसियों, डाॅग स्कवॉड और बम निरोधक दस्ते ने विधानसभा परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाश ली, जांच में विस्फोटक अथवा संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर राहत की सांस ली

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधानसभा को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सघन जांच में यह धमकी पूरी तरह फर्जी पाई गई। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाबी ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत राज्य के पुलिस महानिदेशक को सूचना दी और पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखी। एहतियातन विधानसभा अधिकारियों को खाली कराया गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते और विशेष पुलिस बल ने मौके पर



राजस्थान विधानसभा को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना के सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और डाॅग स्कवॉड ने चप्पे-चप्पे की तलाश ली।



राजस्थान विधानसभा को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना के सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और डाॅग स्कवॉड ने चप्पे-चप्पे की तलाश ली।

■ ई-मेल भेजने वालों की तलाश में जुटी है साइबर एजेंसियां, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी

पहुंचकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। एंटी सबोटाज चेक टीम द्वारा आधुनिक उपकरणों की सहायता से विधानसभा परिसर की गहन जांच की गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को पूरी तरह सुरक्षित बताया और प्रमाण-पत्र भी जारी किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ईमेल की सामग्री भ्रामक और असंबंधित है, जिसका विधानसभा से कोई लेना-देना नहीं है। ईमेल

में कुछ तथ्यहीन और भटकाने वाली बातें लिखी गई थीं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए साइबर एजेंसियों द्वारा खोज का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने विधानसभा अधिकारियों और कर्मचारियों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। जांच पूरी होने के बाद विधानसभा सचिवालय की अधिकारी और कर्मचारी पुनः अपने कार्यस्थलों पर लौट आए और परिसर में सामान्य कामकाज बहाल हो गया।

हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में भी बम विस्फोट की धमकी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में बम विस्फोट करने की धमकी के साथ सोमवार को कोर्ट की आधिकारिक मेल आइडी पर ईमेल भेजे गए। हालांकि हर बार की तरह पुलिस को तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और यह सिर्फ धमकी निकली। जानकारी के अनुसार ग्रीष्मकालीन कोर्ट के पहले दिन सुबह जिला न्यायालय की ऑफिशियल मेल आइडी पर यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इस पर कोर्ट प्रशासन की ओर से स्थानीय थाने सहित आलाधिकारियों को जानकारी दी गई। इसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। इस दौरान हाईकोर्ट प्रशासन को भी धमकी भरा ईमेल भेजा गया। ऐसे में हाईकोर्ट परिसर की भी तलाशी ली गई। दोनों कोर्ट

परिसर में पुलिस की विभिन्न एजेंसियों के आलाधिकारी और डाॅग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान डाॅग स्क्वाड ने कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी सेशन कोर्ट परिसर में करीब आधा दर्जन बार बम विस्फोट की धमकी देते हुए ईमेल भेजे गए हैं। वहीं हाईकोर्ट में सिरफिरी ने एक दर्जन से अधिक बार ऐसे मेल भेजे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा का कहना है कि हर बार मेल मिलने के बाद जांच एजेंसियां आकर परिसर की तलाशी लेती हैं, लेकिन यह सिर्फ धमकी ही साबित होती है। इस दौरान सरकार के लाखों रुपए भी खर्च होते हैं।



बेंगलुरु के बल्लेबाज रजत पाटीदार के खिलाफ गलत गेंदबाजी विकल्प चुनना मुंबई के लिए भारी पड़ गया। उन्होंने कहा कि पाटीदार पहले ही स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इसके बावजूद उन्हें स्पिन के सामने खेलने का मौका दिया गया। - आर. अश्विन

पूर्व भारतीय गेंदबाज, पाटीदार के खिलाफ गलत गेंदबाजी को लेकर बोलते हुए।

आईपीएल 2026 : गुजरात-चेन्नई मुकाबलों का चुनाव के चलते शेड्यूल बदला

मुंबई, 13 अप्रैल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शेड्यूल में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले दो मुकाबलों के वेन्यू आपस में बदल दिए गए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, 26 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद में होने वाला दोपहर का मैच अब चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला अब भी अपने निर्धारित समय दोपहर 3:30 बजे पर ही शुरू होगा। वहीं, 21 मई 2026 को चेन्नई में होने वाला रिवर्स मैच अब अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बीसीसीआई के अनुसार, यह बदलाव गुजरात के अहमदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों में 26 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चुनाव के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देते हुए मैच के वेन्यू को बदलने का निर्णय लिया गया।

प्रीमियर लीग : मैनेज्मेंट सिटी ने चेल्सी को रौंदा, आर्सेनल पर खिताब बचाने का बड़ा दबाव



नई दिल्ली, 13 अप्रैल। मैनेज्मेंट सिटी ने चेल्सी को 3-0 से हराकर प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में खिताब की अपनी उम्मीदों को बनाए रखा। इस जीत से मैनेज्मेंट सिटी शीर्ष पर काबिज आर्सेनल से केवल छह अंक पीछे रह गया है। आर्सेनल के 32 मैच में 70 और मैनेज्मेंट सिटी की 31 मैच में 64 अंक हैं। आर्सेनल शनिवार को बोर्नमाउथ से हार गया था जिसका फायदा मैनेज्मेंट सिटी ने उठाया। स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेलें हुए मैच में मैनेज्मेंट सिटी की तरफ से निको ओरेली (51 वें), मार्क गुइही (57 वें) और जेरेमी डोकू (68 वें मिनट) ने दूसरे हाफ में गोल किए। एक अन्य मैच में संडरलैंड ने टोटेंहम को 1-0 से हराया। यह टोटेंहम को इस सत्र में लीग में 16 वें हार है। वह पिछले 14 मैच में जीत हासिल नहीं कर पाया है। संडरलैंड की तरफ से नोर्डी मुकोले ने 61 वें मिनट में मैच का निर्णायक गोल किया। क्रिस्टल पैलेस ने सेल्हर्स्ट पार्क में न्यूकासल को 2-1 से शिकस्त दी।

तीसरी गुलाबी नगर ओपन चैस टूर्नामेंट 2026 का समापन

जयपुर, 13 अप्रैल। जयपुर के जगतपुरा स्थित स्कूल में 11-12 अप्रैल 2026 को आयोजित तीसरी गुलाबी नगर ओपन चैस टूर्नामेंट 2026 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह प्रतियोगिता स्विस सिस्टम (7 राउंड) के आधार पर खेले गईं, जिसमें शहर एवं प्रदेश के अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया और कुल 60,000 की पुरस्कार राशि वितरित की गई। ओपन कैटेगरी में बेहद रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जहां अर्नव गुप्ता और अनुर चोपल दोनों ने 6 अंक बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया, लेकिन बेहतर टाई-ब्रेक के आधार पर अर्नव गुप्ता विजेता बने, जबकि अनुर चोपल उपविजेता रहे। वहीं वर्निट दीक्षित ने 6 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा शीर्ष खिलाड़ियों में वीर कुमार, प्रणय चौराड़िया, विक्रमादित्य मुखीजा, पवन सेनी, मोहम्मद अमीन खान और शौर्य भार्गव ने भी उल्लेख प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थानों में अपनी हाक बनाई। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने भी शानदार खेल दिखाया, जिसमें अंडर-09 वर्ग में अद्वैत माहेश्वरी, अंडर-11 में युवराज वैष्णव, अंडर-13 में कुन्ज सिंह तथा अंडर-15 में शिवम खेतपाल विजेता रहे। महिला वर्ग में टीशा ब्याडवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सीनियर (60) वर्ग में जकर अखिलेश विजेता बने और बेस्ट अनरेटेड खिलाड़ी का पुरस्कार ईशान खत्री को मिला। एस आर एन स्कूल से ओपन कैटेगरी में देवीक प्रथम संजय बिजोई द्वितीय और धीरेन्द्र तृतीय स्थान पर रहे, गर्लस कैटेगरी में एस आर एन स्कूल से अपूर्वा प्रथम दिव्या द्वितीय और दीपमाला तृतीय स्थान पर रही।

भदोरिया की जीत में भवति, शिवांग, भवानी, राजीव तथा आदित्य चमके

जयपुर, 13 अप्रैल। यूनियन क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 27वीं वनीन नफीस स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के अन्तर्गत नैना क्रिकेट ग्राउण्ड पर खेले गये मैच में भदोरिया क्रिकेट एकेडमी ने प्रथम कुमावत 100 रन नाबाद (86 गेंद 7 चौके 7 छक्के) के शतक तथा शिवांग सिंह 68 रन नाबाद (47 गेंद 6 चौके 5 छक्के) भवानी सुधार 3 रन (43 गेंद 6 चौके 5 छक्के) के अर्द्ध शतको तथा आदित्य चौधरी 50 रन पर 4 विकेट तथा राजीव दुस्ताबा 37 रन पर 3 विकेट की गेंदबाजी की बदौलत नैना क्रिकेट एकेडमी को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया टॉस जीतकर नैना एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जयन्त ताम्बी 51 रन शुभम मीणा 55 रन बेनीप्रसाद 31 रन आशीष शर्मा 38 की पारियों के बावजूद पूरी टीम 37.4 ओवर में 239 रन बनाकर सिमट गई गेंदबाजी में भदोरिया एकेडमी की ओर से आदित्य चौधरी 50 रन पर 4 विकेट राजीव दुस्ताबा 37 रन पर 3 विकेट तथा भवानी सुधार 24 रन पर 2 विकेट लेकर सफल गेंदबाज रही। जवाब पारी में भदोरिया एकेडमी ने भवानी सुधार 63 रन व भवति कुमावत 100 रन नाबाद ने मिलकर 13.3 ओवर में पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़कर शानदार शुरुआत की दूसरे विकेट पर भवति ने शिवांग सिंह 68 रन के साथ मिलकर 135 रन की नाबाद साझेदारी निभाकर अपनी टीम को एकतरफ 9 विकेट से जीत दिला दी।

हैदराबाद ने रोका राजस्थान का विजय रथ प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन को 4-4 विकेट



हैदराबाद, 13 अप्रैल। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का विजय रथ रोक दिया है। एसआरएच ने सोमवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आरआर को 57 रनों से रौंदा। यह राजस्थान

टीम की लगातार चार मैच जीतने के बाद सीजन में पहली हार है।

एसआरएच ने पांच मैचों में दूसरी जीत हासिल की है। एसआरएच ने 217 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में आरआर की पारी 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई।

डेब्यूटेंट प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने गर्दा उड़ाया। प्रफुल्ल ने चार ओवर के स्पेल में 34 रन देकर चार शिकार किए। हुसैन ने स्पेल में 24 रन खर्च किए और चार विकेट चटकाए। ईशान मलिंगा को दो विकेट मिले। राजस्थान की लक्ष्य का पीछा करते हुए हालत खस्ता रही। आरआर ने महज 9 रन जोड़कर पांच विकेट खो दिए थे। हिंगे ने पहले ओवर में तीन शिकार किए। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुआन-डू प्रोटोरियस को खाता ही खोलने दिया।

हिंगे ने तीसरे ओवर में कप्तान रियान पराग (4) को पवेलियन भेजा। हुसैन ने दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल (1) को आउट किया। संकट में डोनोंवन फरेरा (44 गेंदों में 69) और रवींद्र जडेजा (32 गेंदों में 44) ने मोर्चा संभाला और आरआर को जल्द देर होने से बचाया। दोनों ने छठे विकेट के लिए

118 रनों की साझेदारी की। हुसैन ने 15 वें ओवर में फरेरा को बोल्ट कर साझेदारी को तोड़ा। उनके जाल में जोफ्रा आर्चर (2) और रवि बिश्नोई (0) भी फंसे। तुषार देशपांडे ने 11 गेंदों में 25 रन बटोरे। वह आरआर की ओर आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहे।

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम घोषित, जुएरिया नया चेहरा

ढाका, 13 अप्रैल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में 20 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज जुएरिया फडीस को पहली बार शामिल किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में दाएं हाथ की बल्लेबाज शर्मिना सुल्ताना की सात साल बाद एकदिवसीय टीम में वापसी हुई है, जिससे टीम के बल्लेबाजी क्रम को अनुभव मिलेगा। टीम की कप्तानी निगार सुल्ताना जोटी के हाथों में होगी, जबकि नाहिदा अख्तर उपकप्तान रहेंगी। उनका चयन यह संकेत देता है कि चयनकर्ता आगामी व्यस्त सत्र को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को अवसर देना चाहते हैं। श्रीलंका की टीम 17 अप्रैल को बांग्लादेश पहुंचेगी और सीधे राजशाही जाएगी, जहां वनडे सीरीज का आयोजन होगा। दोनों टीमों में सीरीज से पहले दो दिन अभ्यास करेंगी। तीन मैचों की यह शृंखला 20, 22 और 25 अप्रैल को राजशाही डिवीजनल स्टेडियम में खेली जाएगी। सभी मुकाबले सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे। इसके बाद 26 अप्रैल से दौरा सिलहट में होगा, जहां तीन मैचों की 20-20 सीरीज सिलहट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। श्रीलंका की टीम 3 मई को दौरा समाप्त कर वापस लौटेगी। बांग्लादेश एकदिवसीय टीम : निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), नाहिदा अख्तर (उपकप्तान), फरजाना हक, शोभना मोस्ट्री, फहीमा खातून, शारमिन अख्तर सुल्ता, रिंतु मोनी, शोर्ना अख्तर, राबेया खान, शर्मिन सुल्ताना, मरुफा अख्तर, फरिहा इस्लाम त्रिस्ना, सुल्ताना खातून, शांजिदा अख्तर माचला, जुएरिया फडीस।

रोहित की हैट्रिक से जयपुर सिटी जीता

जयपुर, 13 अप्रैल। राजस्थान फुटबॉल संघ और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में जारी आर लीग डिवीजनल फुटबॉल लीग के आज तीसरे मैच खेले गए। पहला मैच ब्रदर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और ए स ल के बीच मैच खेला गया। जिसमें ब्रदर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने एकतरफ अंदाज में 3-0 से मैच अपने नाम किया। मैच के 8 मिनट में विशाल ने पहला गोल किया दूसरा गोल मैच के 26 मिनट में हर्ष ने किया। मैच का अंतिम गोल विष्णु ने 61 मिनट में किया। दूसरे मैच जिक फुटबॉल अकादमी और सनराइज फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। जिसमें जिक ने सनराइज को 4-1 से हराया जिक की तरफ से विशाल (14 मिनट) करण (42 मिनट) मध्यांतर के अतिरिक्त समय में मनीष (45 5 मिनट) यश (56 मिनट) में गोल किया। सनराइज की तरफ से एकमात्र गोल आशीष (25 मिनट) में किया।

आरसीए एडहॉक कमेटी ने घरेलू क्रिकेट कैलेंडर 2026-27 की रुपरेखा के लिए गठित की कमेटी : डॉ. मोहित

आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र में खिलाड़ियों की एनओसी, बेन प्रक्रिया के संबंध में जिला क्रिकेट संघों को जारी किये दिशा-निर्देश

जयपुर 13 अप्रैल। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डॉ मोहित जसवंत यादव के अनुसार पदवार ग्रहण करने के बाद से ही हमारा प्रथम प्रयास है की राज्य में क्रिकेट को नई उंचाईयों पर लाकर खिलाड़ियों की समस्त समस्याओं को दूर किया जाये व उन्हें एक बेहतर खेल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डॉ मोहित सदस्य धनजय सिंह खींवर, आशीष तिवारी, अर्जुन बेनीवाल, अरिष्ट सिंघवी और सीए क्रिकेट गतिविधियों की समस्त रूपरेखा व आरसीए के घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 के क्रिकेट कैलेंडर व उसके निश्चित समयाविधि को तैयार करने के लिए पूर्व खिलाड़ी व एडहॉक कमेटी सदस्य अरिष्ट सिंघवी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है

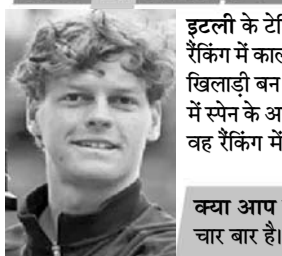
व निर्देश दिए हैं की कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर आरसीए एडहॉक कमेटी को प्रस्तुत करेगी जिससे राज्य की क्रिकेट गतिविधियों के आयोजन में व्यापक सहयोग मिलेगा। आरसीए एडहॉक कमेटी द्वारा गठित कमेटी :- अध्यक्ष - अरिष्ट सिंघवी, सदस्य - विजेंद्र यादव, राजीव राठी, सुमित माधुर, ओ पी शर्मा, पूनम यादव, एकता प्रमोद सिंहा एडहॉक कमेटी सदस्य धनजय सिंह खींवर के अनुसार एडहॉक कमेटी ने आरसीए के सभी जिला क्रिकेट संघों को वित्तीय वर्ष 2023 - 24 व 2024 - 25 की ऑडिट रिपोर्ट आरसीए कार्यालय को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं साथ ही जिला संघों द्वारा जिले में आयोजित की जाने वाली क्रिकेट गतिविधियों, प्रशिक्षण शिविर, चयन ट्रायल व चयन प्रक्रिया

की समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। एडहॉक कमेटी सदस्य आशीष तिवारी के अनुसार आरसीए एडहॉक कमेटी का प्रयास यही है की राज्य में क्रिकेट का चहुमुखी विकास व विस्तार हो व राज्य के युवा खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट सत्र में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो पर आरसीए एडहॉक विशेष ध्यान रख रही है। इसी कड़ी में आरसीए एडहॉक कमेटी ने आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र की क्रिकेट गतिविधियों से सम्बंधित समस्त कार्यों की जिम्मेदारी एडहॉक कमेटी सदस्य अरिष्ट सिंघवी को दी गयी है। अरिष्ट सिंघवी से समस्त राज्य के विभिन्न युवा खिलाड़ियों ने संपर्क कर घरेलू क्रिकेट सत्र के दौरान होने वाली विभिन्न समस्याओं के सम्बद्ध में अवगत कराया। आशीष तिवारी की अनुसार आरसीए एडहॉक कमेटी ने इसपर

गहन विचार करते हुए आरसीए के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र के लिए एडहॉक कमेटी सदस्यों की सर्वसम्मति से सभी जिला क्रिकेट संघों को निम्न निर्देश जारी किये हैं :- राज्य के सभी खिलाड़ियों पर लगाए गए बैन को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। खिलाड़ियों पर किसी भी प्रकार का बैन या प्रतिबन्ध बिना राजस्थान क्रिकेट संघ की सहमति के मान्य नहीं होगा। यदि जिला क्रिकेट संघ खिलाड़ी को किसी भी परिस्थिति में अन्य जिले से खेलने के लिए आवश्यक एनओसी देने में असफल होता है तो खिलाड़ी सीधे राजस्थान क्रिकेट संघ से संपर्क कर एनओसी के लिए आवेदन कर सकता है व संबंधित जिला क्रिकेट संघ को एनओसी से सम्बंधित अपनी आपत्त मय आवश्यक दस्तावेज व कारण सहित आरसीए को उपलब्ध करानी होगी।

यानिक सिनर

आज का खिलाड़ी



इटली के टेनिस स्टार यानिक सिनर नई एटीपी टेनिस एकल रैंकिंग में कार्लोस अल्कारेज को पछाड़कर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर ने मॉंटे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में स्पेन के अल्कारेज को हराकर खिताब जीता था जिसके बाद वह रैंकिंग में टॉप पहुंच गए हैं। बले कोर्ट पर यह सिनर का

क्या आप जानते हैं ? ... वॉरेंडर सहवाग का नाम टेस्ट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वालों की सूची में टॉप-10 में चार बार है।

आईपीएल डग आउट में फोन इस्तेमाल, राजस्थान रॉयल्स मैनेजर रोमी भिंडर पर एसीयू का शिकंजा, जांच तेज

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। आईपीएल के बीच एक नया विवाद सामने आ गया है, जिसने क्रिकेट प्रशासन और नियमों को लेकर बहस तेज कर दी है। राजस्थान टीम के प्रबंधक रोमी भिंडर से जुड़ा मोबाइल फोन मामला अब गंभीर रूप ले चुका है और इस पर औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि गुवाहाटी में खेले गए एक मुकाबले के दौरान रोमी भिंडर टीम के विश्राम क्षेत्र में बैठे हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। यह नियमों के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार टीम प्रबंधक केवल ड्रेसिंग रूम के अंदर ही मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। विश्राम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल केवल अधिकृत विश्लेषक को ही अनुमति होती है। मौजूद जानकारी के अनुसार, इस मामले पर क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने संज्ञान लिया है और रोमी भिंडर को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच



कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। गौरतलब है कि इस मामले में एक नया पहलू भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, मोबाइल फोन के इस्तेमाल के पीछे एक चिकित्सकीय आपात स्थिति हो सकती है। बताया जा रहा है कि रोमी भिंडर पहले भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुझ चुके हैं, जिसमें फेफड़े से जुड़ी बीमारी शामिल रही है। इसके अलावा उन्हें दमा की भी परेशानी बताई जा रही है, जिसके कारण उन्हें ज्यादा चलने या सीढ़ियां चढ़ने से बचने की सलाह दी गई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि उनके पास मोबाइल फोन रखने की लिया है और रोमी भिंडर को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच

निर्धारित स्थान पर ही किया जा सकता है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह नियमों का उल्लंघन जानबूझकर हुआ या परिस्थितियों के चलते ऐसा करना पड़ा।

इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने मामले को और तूल दे दिया है, जिसमें उनके पास बैठे एक अन्य सदस्य को भी फोन की स्क्रीन की ओर देखते हुए देखा गया। इसके बाद इस घटना को लेकर सवाल उठाने लगे और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। मौजूद हालात यह संकेत देते हैं कि खेल में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना कितना जरूरी है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी फैसले से पहले सभी पहलुओं, खासकर स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे यह साफ हो सकेगा कि यह मामला नियमों के उल्लंघन का है या फिर एक मजबूरी में लिया गया फैसला है।

क्या फिर वीआईपी पार्किंग की किक लगेगी फुटबॉल मैदान को ?



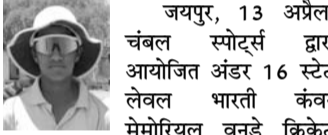
जयपुर, 13 अप्रैल। सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के आयोजन में आने वाले वीआईपी लोगों के लिए फुटबॉल मैदान को पार्किंग में तब्दील कर दिया जाता है। दक्षिणी गेट से प्रवेश करने वाले दर्शकों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था स्टेडियम के अंदर रहती है। खेल ग्राउंड में आरसीए पदाधिकारी व सदस्यों के

वाहनों की पार्किंग रहती है। आईपीएल सीजन के चलते फुटबॉल खिलाड़ियों के अभ्यास पर भी रोक लगा दी जाती है। जबकि आईपीएल मैचों से फुटबॉल खिलाड़ियों का कोई लेना-देना नहीं है। 20 खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है और गेट के बाहर से भेज दिया जाता है। आईपीएल मैचों के दौरान हर बार

इन मैदान पर सैकड़ों चौपटिया वाहन खड़े किए जाते हैं, जिस कारण मैदान पूरी तरह खराब हो जाता है। जबकि खिलाड़ी मिलकर मैदान को खेलने लायक बनाते हैं और क्रिकेट मैचों में होने वाली पार्किंग से फुटबॉल मैदान पर की गई सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

जयपुर में आईपीएल मैचों के लिए एसएमएस स्टेडियम के दो मैदानों को तबाह कर दिया जाएगा। क्रिकेट मैच के लिए आरसीए स्टेडियम के पास स्थित फुटबॉल और निशानेबाजी मैदान पर वीआईपी गाड़ियों के लिए पार्किंग बना दी जाएगी। इसके कारण दोनों मैदानों की घास खराब होगी। यहाँ हर रोज कम से कम 100 खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है और गेट के बाहर से भेज दिया जाता है। आईपीएल मैचों के दौरान हर बार

समक्ष के पंजे से जयपुरिया क्रिकेट अकादमी ने संस्कार क्रिकेट अकादमी को हराया



जयपुर, 13 अप्रैल। चंबल स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित अंडर 16 स्टेड लेवल भारतीय कंबर मेमोरियल वनडे क्रिकेट लीग में संस्कार क्रिकेट अकादमी और जयपुरिया क्रिकेट अकादमी के मध्य मुकाबला खेला गया। जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए संस्कार क्रिकेट अकादमी ने 23.1 ओवर में 54 रनों पर ऑल आउट हो गई। जिसमें मानीक शर्मा ने 11 रन व हर्षित धस्माना ने 7 रन बनाए। जयपुरिया क्रिकेट अकादमी की गेंदबाजी की ओर से समक्ष जैन ने 5 विकेट व कुशाग्र उपाध्याय ने 2 विकेट लिए। जवाब में जयपुरिया क्रिकेट अकादमी ने मात्र 8.5 ओवर में 55/3 रन बनाकर जीत हासिल की। जिसमें रचित परेल ने 27 रन व खाश्वित वर्माने ने 18 रन की पारी खेली। संस्कार क्रिकेट अकादमी की गेंदबाजी की ओर से पुलकिम माधुर ने 2 विकेट व जयपूर सिंह कोहली ने 1 विकेट लिया। जयपुरिया क्रिकेट अकादमी ने 7 विकेट से मुकाबला जीता।

भारत में फिर गुंज सकती है फॉर्मूला वन की रफतार : मनसुख मांडविया

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि वह भारत में 2027 तक फॉर्मूला 1 की वापसी को लक्ष्य बना रहे हैं। इसके लिए उन कर संबंधी बाधाओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिनकी वजह से 2013 के बाद यह रस भारत से बंद हो गई थी। मीडिया से बातचीत में मांडविया ने बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर रस कराने की योजना है और कम से कम तीन कंपनियों ने इस ट्रैक के संचालन में रुचि दिखाई है। मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में 2027 में फॉर्मूला वन रस होगी और पहली रस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार आयोजकों के लिए इस परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए टैक्स में राहत देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि इस पर अगले छह

महीनों में विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, खासकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत को खेल आयोजकों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर विकल्प माना जा रहा है। सरकार पहले मोटो जीपी रेस आयोजित करने की योजना बना रही है, उसके बाद फॉर्मूला वन की वापसी का रास्ता तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में इंडियन ग्रां प्री 2011 से 2013 तक तीन बार आयोजित हुआ था, लेकिन टैक्स और प्रशासनिक दिक्कतों के चलते इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि, फॉर्मूला वन के मालिक लिबर्टी मीडिया से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2027 में रस होना फिलहाल मुश्किल रहेगा है, लेकिन भारत एक बड़ा संभावित बाजार जरूर है। भारत में पहले भी बड़े मोटरस्पोर्ट आयोजन लंबे समय तक नहीं चल पाए हैं।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन सशो अशिशु विभागा, खण्ड धौलपुर मरकुक धौलपा जी0टी0शेड धौलपुर फोन नं. 05642-220728 ई-मेल ee.dho.pshed@rajasthan.gov.in

क्रमांक -153-160 दिनांक - 09-04-2026 ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-27 NIB No. PWD2627A0096 राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड के अधीन विभिन्न कार्यों की उपरोक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निरासित प्रयत्र में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्न यू. वी. एन. के अनुसार www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.rajwater.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउन लोड भी किये जा सकते हैं। एन.आई.वी.नं. - PHE2627A0119 यू. वी. एन. PHE2627WS0B00200

DIPRC/G/6784/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभागा खण्ड जालौर क्रमांक: अअ/अ/2026-27/87 दिनांक: 09.04.2026 निविदा सूचना संख्या : 01 वर्ष 2026-27 NIB No. PWD2627A0096

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन निर्माण कार्य हेतु उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभागा राजस्थान में पंजीकृत संवेदको एवं राज्य सरकार / केंद्र सरकार के अधिष्ठित संगठनों / केंद्रीय लोक निर्माण विभागा/डाक एम्वर दूर संचार विभागा / रेवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको, जो कि राजस्थान सरकार के उपर्युक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रयत्र में 5 करोड़ जिनकी लागत राशि रु. 91.02 लाख है, अतः उक्तकार्यों के लिए ईटेंडरशिप प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदा आवेदन डाउनलोड 13 अप्रैल 2026 प्रातः 10.00 बजे से 20 अप्रैल 2026, सायं 6:00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साइट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। वृत्त संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताकर के माध्यम से वेबसाइट पर http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। NIB No. PWD2627A0096 यू. वी. एन. -1. PWD2627WS0B00433. 2. PWD2627WS0B00436 3. PWD2627WS0B00438. 4. PWD2627WS0B00440. 5. PWD2627WS0B00442

(कारक लाला) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड, जालौर मोबाईल 9893975907

DIPRC/G/6783/2026

मुख्यमंत्री ने पचपदरा में प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की जनसभा में पानी, बैठने तथा पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए

बालोतरा/जयपुर, 13 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बालोतरा में पचपदरा की एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बालोतरा में प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को देश के पहले एचपीसीएल इंडीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ बालोतरा में करेंगे। इस रिफाइनरी के माध्यम से देश-प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही, यह रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा।

इस दौरान शर्मा ने रिफाइनरी की क्लूड डिजिटेशन यूनिट, रिफाइनरी में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने रिफाइनरी प्रतिनिधियों से संवाद कर उनका अनुभव भी जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बालोतरा के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जनसभा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन स्थल के ले आउट का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को सुरक्षा के विशेष

इंतजाम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी का निरीक्षण कर आयोजन स्थल पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक दल के नेता, यानी राज्य के नए मुख्यमंत्री को सुरक्षा के विशेष

बैठक भी ली। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए जनसभा में आमजन के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग आपस में

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफायनरी की क्लूड डिजिटेशन यूनिट, रिफायनरी में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने रिफायनरी के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके अनुभवों की जानकारी ली।

समन्वय कर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल पर सजावट में राजस्थान की कला संस्कृति का प्रदर्शन होना चाहिए, जिससे आगन्तुक प्रदेश की ऐतिहासिक गौरवशाली परम्परा से रूबरू हो सकें। इससे पहले हैलिपेड पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री श्री जोराम कुमावत, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री केके बिर्नोई, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कई अन्य नेता, मंत्री व अफसर मौजूद थे।

गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया तो उम्र कैद व 25 लाख रूपए तक जुर्माना

पंजाब विधानसभा में सर्व सम्मति से बेअदबी कानून पारित

चंडीगढ़, 13 अप्रैल। पंजाब में करीब एक दशक से चुनावी मुद्दा बने बेअदबी के मामलों में अब कड़ी सजा देने के लिए सोमवार को बेअदबी कानून पारित किया गया है। बैसाखी के अवसर पर पंजाब विधानसभा के विशेष एक दिवसीय सत्र के दौरान विधानसभा में जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 सर्वसम्मति से पास किया गया। इस विधेयक में आरोपितों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में यह विधेयक पेश किया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक अभी केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर ही लागू होगा। गैर सिखों (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदि) के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ पर इस विधेयक के तहत फिलहाल कोई सजा का प्रावधान नहीं है। सीएम ने कहा कि अन्य धर्मों के लोगों से भी राय लेकर जल्द ही कानून बनाया जाएगा।

इस विधेयक को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और स्पीकर कुलतार सिंह संघों के बीच बहस हुई। बाजवा ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन इस मामले में

■ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, अब कोई पत्थर दिला ही होगा, जो ऐसा करने के बारे में सोचेगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो पीढ़ियों तक उसका अहसास रहेगा।

बनाई गई निज्जर कमेटी की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाए। इससे पहले अप्रैल, 2025 में एक विधेयक लाया गया था, जिसमें सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को शामिल किया गया था, लेकिन उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। वर्तमान पारित विधेयक केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर केंद्रित है। सत्र के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने पर सख्त सजा रखने संबंधी बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अब कोई पत्थर दिला ही होगा, जो इस घटना के बारे में सोचेगा। अगर सोचेगा तो उसे पीढ़ियों तक उसका अहसास रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सेलेक्ट कमेटी का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया है,

क्योंकि उस समय बाढ़ आ गई थी। ऐसे में सभी धर्मों के लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। अभी सभी से राय लेनी होगी। कमेटी अब सभी धार्मिक लोगों के पास जाकर राय लेगी।

‘अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) देते हुए, न्यायमूर्ति ने कहा, “आप जिस देश में पैदा हुए हैं, वहां मतदान का अधिकार केवल संवैधानिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। यह ऐसा है, जैसे आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं और सरकार चुनने में मदद कर रहे हैं।” जब नायडू ने कहा कि पश्चिम बंगाल किसी भी दृष्टिकोण से एसआईआर वाले राज्यों की तुलना में अलग नहीं है, तो न्यायमूर्ति वागची ने कहा कि बिहार में तार्किक असंगति सूची नहीं थी। नायडू ने कहा कि बिहार में भी अस्वीकृतियां हुईं, लेकिन कोई अपील प्रक्रिया नहीं थी। इस पर न्यायमूर्ति वागची ने कहा, “अपील न्यायाधिकरण के लिए यह मतदाता सूचियों को बढ़ाने या घटाने का मुकाबला नहीं है। उन्हें समावेशन के सिद्धांतों पर सुनवाई करनी होगी।”

‘तृणमूल अलगाववादियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अलगाववादियों के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए दोषी ठहराया। देश की सुरक्षा के प्रति टीएमसी की “अविकेकपूर्ण नीति” का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा: “हमारा सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण द्वार है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि भारत माता की भुजा है। लेकिन दोस्तों, आंखों को खोलना चाहिए कि तृणमूल ने चोट बैक को खुश करने के लिए क्या-क्या किया?”

उन्होंने आगे कहा, “देश में एक टुकड़े-टुकड़े गैंग (अलगाववादी) है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। उन्होंने उत्तर-पूर्व को देश से अलग करने की बातें की थीं। ऐसे लोगों को तृणमूल ने सड़क से संसद तक समर्थन दिया।” सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अनौपचारिक रूप से चिकन नेक कहा

जाता है, मुख्य भारत को उत्तर-पूर्व से जोड़ता है। यह रास्ता अपने सबसे संकीर्ण हिस्से पर लगभग 20-22 किमी चौड़ा है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन की सीमा के करीब स्थित है। बंगाल के मंत्री और तृणमूल उम्मीदवार ब्रज्य बसु ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “वे हर उस व्यक्ति को टुकड़े-टुकड़े गैंग कहते हैं जो भाजपा के खिलाफ है।”

कांग्रेस ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सरकार संसद के मौजूदा बजट सत्र के तहत हो रही इस तीन दिवसीय बैठक में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने से संबंधित संशोधन एवं परिशीलन से जुड़े विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है।

15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार का गठन होगा

पटना, 13 अप्रैल। बिहार में नयी सरकार के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार दोपहर 2 बजे जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक दल की बैठक अपने आवास पर बुलाई है।

वहीं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने करीब 3:30 बजे अपने विधायकों की बैठक तय की है, जिसमें केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक दल के नेता, यानी राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। दोनों दलों की बैठकों के बाद शाम 4 बजे विधानमंडल के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें भाजपा विधायक दल के नेता को गठबंधन का नेता चुना जाएगा।

■ नीतीश 14 अप्रैल को राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे।

भाजपा और जदयू सूत्रों के अनुसार, बिहार में करीब पांच माह के भीतर नई सरकार का गठन 15 अप्रैल को किया जाएगा और उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने की संभावना है। इधर, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर सोमवार को राजग नेताओं की अहम बैठक हुई। जदयू नेता संजय झा और लल्लन सिंह ने उनसे मुलाकात की, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी भी वहां पहुंचे। फिलहाल सरकार गठन की गतिविधियों का केन्द्र नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के आवास बने हुए है।

‘कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ है, हम इरेंगे नहीं’

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिकी भुइयां पर लगाए गए आरोपों के बाद दर्ज हुई एफआईआर मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ खड़ी है।

राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि सरमा अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए अपनी मुख्यमंत्री की सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह संविधान के खिलाफ है।

चीन ने अरुणाचल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया, “अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा।”

समझा जाता है कि भारतीय सरकार ने चीन से आग्रह किया है कि वह ऐसे कदम न उठाए, जो द्विपक्षीय संबंधों में नकारात्मकता पैदा करें और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “चीन की ये कार्रवाहियां भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और सामान्य करने के प्रयासों से ध्यान भटकती हैं।”

पिछले वर्षों में, चीन ने अपने सिविल अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट पर अरुणाचल के स्थानों के नाम चीनी और तिब्बती लिपि में प्रकाशित किए हैं, साथ ही उनके अक्षांश/देशांतर और नक्शे भी दिए हैं। ये स्थान भारतीय प्रशासनिक जिलों, जैसे तवांग, वेस्ट

कामेंग, सियांग, अंजाव, डिबांग वैली आदि में आते हैं। चीन का यह भी कहना है कि अरुणाचल तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है और मैकमोहन रेखा “अवैध और शून्य है।” यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उत्पाद है, जिसे तिब्बत (स्वतंत्र इकाई नहीं) को स्वीकार करने का अधिकार नहीं था। भारत ने लगातार एकतरफा बदलाव को खारिज किया है और जोर देकर कहा है कि अरुणाचल और लद्दाख दोनों भारत के अपरिहार्य मुख्य हित हैं।

कूनो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रेंज से मोहम्मद अखलाक, जितेन्द्र सहरिया, बलराम सहरिया आदि वनकर्मी साथ थे। बताया जा रहा है कि चीता एक नीलगाय का शिकार कर चुका है।

अमेरिका ने जहाजों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कुछ संकेत हैं कि नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों पर लागू होगी। अमेरिकी नौसेना ने पहले ही संदेश भेज दिए हैं कि कोई भी ईरानी जहाज, जो खाड़ी के माध्यम से या होर्मुज की ओर बढ़ रहा है, उसे समायोजन कर दिया जाएगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रहा है और इन्हें निष्क्रिय किया जा रहा है। यह मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के बीच संघर्ष विराम को खतरे में डाल सकता है और वे एक-दूसरे पर हमले शुरू कर सकते हैं। ईरान अपनी ओर से अन्य प्रकार के हस्तक्षेप की कोशिश कर रहा

है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद पेझेशकियन ने व्लादीमिर पुतिन से संपर्क किया है, ताकि विवादों को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया जा सके। होर्मुज नाकेबंदी ईरान के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान अपने कच्चे तेल को होर्मुज के मार्ग से ही भेजता रहा है। इसके अलावा, हिंसा के फैलने के बाद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने ईरान को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में मदद की, जिससे उसने अपनी कार्रवाहियों को वित्तपोषित किया।

बंगाल में एक्शन मोड़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) राजनीतिक दिग्गजों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कोर्पोरेट संस्थाओं को निशाना बनाया, और हवाला लेने देन और “अपराध की आय” का एक व्यापक नेटवर्क उजागर किया। एजेंसी की नजर उच्च पदस्थ अधिकारियों पर कड़ी हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एजेंसी ने कई घोटालों में कथित रूप से शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मेडिकल पती घोटाले के अन्तर्गत, संतनु सिन्हा बिस्वास, पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा, कोलकाता), अपने बेटे

को कथित रूप से निजी मेडिकल कॉलेज में घोखाघड़ीपूर्ण एनआरआई के तहत प्रवेश दिलाने के आरोप में जांच के घेरे में हैं। समन को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने के बावजूद, ईडी ने उनकी उपस्थिति के लिए नए आदेश जारी किए हैं, यह कहते हुए कि जांच पर कोई रोक नहीं है।

‘सरकार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे रोकने के लिए अपनी कमर कस ली है। विशेषकर दक्षिण भारत की पार्टियां, जिन्हें लगता है कि वे हाशिप पर आ जाएंगी, और छोटे राज्यों को, जिन्हें लगता है कि वे राष्ट्र शासन में अप्रासंगिक हो जाएंगे, परिसीमन के कारण इस विधेयक के कड़े रूप से शामिल

मॉनसून में सामान्य से कम बारिश का अनुमान

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 को लेकर शुरुआती पूर्वानुमान जारी किया है। इस बार देश में मानसूनी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। जून से सितंबर के बीच होने वाली कुल वर्षा लगभग 92 प्रतिशत लॉन्ग परियर्ड एवरेज (यानी किसी क्षेत्र में

■ मौसम विभाग की शुरुआती रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ें।

एक निश्चित अवधि में 30 या 50 वर्षों की दर्ज की गई औसत वर्षा) रहने का अनुमान है, जिसमें 5 प्रतिशत की संभावित त्रुटि हो सकती है। देश के लिए

एलपीए (1971-2020 के आधार पर) 87 सेंटीमीटर तय है। आईएमडी ने सोमवार को जारी पूर्वानुमान में बताया कि फिलहाल प्रशांत महासागर में कमजोर ला नीना जैसी स्थिति बनी हुई है, जो धीरे-धीरे इंफ्लूएन्स न्यूट्रल की ओर बढ़ रही है। हालांकि, मानसून सीजन के दौरान एल नीनो बनने की संभावना जताई गई है।

आशा भोंसले पंचतत्व में विलीन हुईं, बेटे ने मुखार्गि दी

महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गाई ऑफ ऑनर दिया

मुंबई, 13 अप्रैल। भारतीय संगीत की दिग्गज गायिका आशा भोंसले सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गईं। 92 वर्ष की आयु में रविवार को मुंबई के ब्रीच कैन्डी अस्पताल में मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हो गया था। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर है।

सोमवार को उनके पार्थिव शरीर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक लोअर परेल् स्थित उनके निवास कासा ग्रांटे में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया।

इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा दादर स्थित शिवाजी पार्क के लिए रवाना हुई। करीब पांच किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर हजारों प्रशंसकों का हजूम उमड़ पड़ा। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने अपनी प्रिय ‘आशा ताई’ को फूलों की वर्षा कर भावभीनी विदाई दी। आशा भोंसले का पार्थिव शरीर फूलों से सजी गाड़ी में शिवाजी पार्क ले

■ सफेद और पीले फूलों से सजी गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया गया जहां उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।

जाया गया। गाड़ी को उनके पसंदीदा सफेद और पीले फूलों से सजाया गया था। उस पर उनकी एक बड़ी तस्वीर लगी थी।

जैसे ही उनका पार्थिव शरीर वाहन में रखा गया, पुलिस बैंड ने शोक धुन बजाकर उन्हें सम्मान दिया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम यात्रा शिवाजी पार्क पहुंची, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।

‘महामानव ‘नीतीश’ के बिना बिहार अधूरा है’

पटना, 13 अप्रैल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को संभवतः अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हम के संस्थापक एवं केन्द्रीय मंत्री जीवन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने से पहले

■ केन्द्रीय मंत्री और ‘हम’ पार्टी के संस्थापक जीवन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश के सी.एम पद से इस्तीफा देने से पहले भावुक ‘पोस्ट’ डाला।

भावुक पोस्ट कर अपने भावनाएं साझा की है। नीतीश कुमार को महामानव बताते हुए उन्होंने कहा है कि उनके बिना बिहार अधूरा रहेगा।

अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सोमवार को उन्होंने कहा कि नीतीश जी, अगले चौबीस घंटे में आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे। सबको पता है कि आपका यह ख़ाब था कि आप देश के चारों सड़कों के सदस्य रहें, पर आपके इस ख़ाब ने करोड़ों दिलों को रूला दिया है।

टोंक, 13 अप्रैल। पूर्व उपमुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट सोमवार को टोंक पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में माला पहनाकर और साफा बंधवाकर कर उनका स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने कहा कि गांवों, शहरों और युनिवर्सिटी में भी चुनाव कराए जाने चाहिए, वर्तमान में प्रशासक और अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं।

भाजपा सरकार के आने के बाद से पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं और विश्वविद्यालयों के चुनाव नहीं कराए गए हैं, जबकि यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, जो संविधान में भी अंकित है। पायलट ने कहा कि विपक्षी विधायकों तथा सांसदों के बजट में भेदभाव होता है, लेकिन हम जनता के काम करवाएंगे। उन्होंने बताया कि टोंक के लिये मेडिकल कॉलेज, पुल और नर्सिंग कॉलेज जैसे कई प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें अपेक्षित स्तर पर औपचारिक शुरुआत नहीं मिल पाई। कानूनी रूप से भी सरकार पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन न तो निर्वाचन आयोग और न ही सरकार इस दिशा में गंभीर दिख रही है। कोर्ट ने 15



पूर्व उपमुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को टोंक के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।

अप्रैल तक चुनाव कराने की समय सीमा दी थी, इसके बावजूद सरकार चुनाव नहीं करा पाई। लगाएने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, क्योंकि उसे डर है कि परिणाम उसके पक्ष में नहीं

आएंगे। लोग चाहते हैं कि बाई मंबर और सरपंच चुने जाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर काम तेजी से हो सके। हाल ही में पायलट ने जिन गांवों का दौरा किया, वहां मनरेगा का काम लगभग खत्म होता नजर आया। सरकार

की मंशा ही मनरेगा को समाप्त करने की है और इसका नाम बदलकर इसे कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान लाखों लोगों को इस योजना से रोजगार मिलता था, लेकिन अब ग्रामीण विकास के कार्यों में गिरावट